

## स्पोर्ट्स 12

सलीमा होंगी भारतीय महिला  
हॉकी टीम की कप्तान

www.dailypioneer.com

## 2025 में होगी जनगणना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नरेंद्र मोदी सरकार 2025 में लंबे समय से लंबित जनगणना शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गण्डियार्पण परिसीमन प्रक्रिया होगी, जिसके 2028 तक समाप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सामाजिक जनगणना के साथ-साथ जाति-जनगणना भी की जाएगी या नहीं।

यह घटनाक्रम कई विपक्षी दलों की ओर से जाति-जनगणना की मांग के बीच समाप्त आया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और जनगणना प्रक्रिया का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आगामी जनगणना की मांग के बीच समाजिक जाति-जनगणना के अनुसूचित जाति-जनगणना की उम्मीद है। आगामी जनगणना के साथ-साथ धर्म और सामाजिक वर्ग पर सामाजिक सर्वेक्षण शामिल होने की उम्मीद है।

विवरण से अवगत लोगों के अनुसार, सरकार ने अभी तक जाति-जनगणना पर कोई निर्णय नहीं लिया है। देश की जनसंख्या का सारणीय बढ़दा करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के प्रक्रिया शुरू होगी। प्रियंका जनगणना 2021 में की गई थी, और अगले दौर की शुरूआत में 2021 के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे लिए निर्वाचन क्षेत्रों के प्रक्रिया शुरू होगी। प्रियंका जनगणना 2020 में की गई थी, और अगले दौर की शुरूआत में 2021 के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे लिए निर्वाचन क्षेत्रों के प्रक्रिया शुरू होगी।

जनगणना और एनपीआर का काम अगले साल की शुरूआत में सुरू हो जाएगा और जनसंख्या के अंकड़े 2025 तक घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनगणना चक्र में बदलाव होने की संभावना है। इसलिए, यह 2025-2035 और फिर 2035-2045 और भविष्य में इसी तरह होगा। उन्होंने कहा कि पर्सीसीमन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले इन सभी कारकों पर विचार करना होगा।

जनगणना अभ्यास के तहत प्रत्येक परिवार से पूछे जाने वाले 31 स्वालों में घर में सामाजिक रूप से रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या घर की मुखिया एक महलाई है, घर के कब्जे में विशेष रूप से रहने वाले कमरों की संख्या, घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या आदि।

शामिल होने के अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और जनगणना प्रक्रिया का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आगामी जनगणना की मांग के बीच समाजिक वर्ग पर सामाजिक सर्वेक्षण शामिल होने की उम्मीद है।

विवरण से अवगत लोगों के अनुसार,

सरकार ने अभी तक जाति-जनगणना पर कोई निर्णय नहीं लिया है। देश की जनसंख्या

का सारणीय बढ़ा करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है,

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

लिए निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद है।

जिसके बाद प्राप्तिसमान के माध्यम से लोकसभा के

काम अगले दौर की उम्मीद ह

# तीनों प्राधिकरणों की एक जैसी औद्योगिक भूखंड नीति साक एंड एसोशिएट को मिली थी जिम्मेदारी, एसओपी तैयार करने के लिए समिति गठित

● 58 सेवटों को  
मिलेगा गंगाजल, बार्यर्स  
की होगी दिजिस्ट्री, बोर्ड ने  
लिया निर्णय

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक प्लाट के आवंटन की पॉलिसी एक समान होगी। इनमें प्राधिकरण की तरफ से साक एंड एसोशिएट को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इससे पहले एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेसिजर) तैयार करने के लिए तीनों प्राधिकरण की एक समिति बनाई गई। जिसकी बैठक में तीनों प्राधिकरण की तरफ से नियंत्रक एवं महाप्रबंधक की बैठक हुई, जिसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया, लोज



रेट व अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में एक सेवटों लाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बोर्ड ने तीनों प्राधिकरण के लिए नियंत्रक एवं महाप्रबंधक की बैठक हुई, जिसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया, लोज

था कि 8000 वर्गमीटर तक औद्योगिक भूखंड का आवंटन इन और उससे ज्यादा के भूखंड नहीं आया। एसओपी प्राप्त अभी सामने नहीं आया है। पूर्व में हुई बैठक में बताया गया

बोर्ड ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के अलावा सबसीकेंट मैंबर्स को भी बी रहा दी गई है। अब ऐसे खरीदारों के नाम भी फैले की रजिस्ट्री हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई है।

इस सोसाइटी में कुल 845 प्लैट हैं, जिनमें से 190 प्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। प्राधिकरण की तरफ से सोसाइटी परिसर में ही शिविर लगाया रजिस्ट्री की जा रही है। ताकि दोनों ग्रेटर नोएडा सीटीजन सोसाइटी के नाम ग्रेटर नोएडा के पास-4, बिल्डर्स एरिया में 1997 में भूखंड दिया गया। विवादों के चलते 27 सालों तक इसी की जायपूर्ति न हो पाने के कारण इसके सदस्यों के पक्ष में योगी डीड नहीं हो पाए। इस प्रूफ मुख्यमंत्री वायर बनाने का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक ये रिजिव वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजिव वायर बनाना का काम चल रहा है।

सिंह व सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रसास से विगत मार्च 2024 से इसकी रजिस्ट्री शुरू हो सकी। जल विभाग की तरफ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के गंगाजल की स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके अनुसार 85 व्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 55 आवासीय सेक्टरों में से अब तक 50 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

बर्ही, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तीन रिजिव वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजिव वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजिव वायर बनाना का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक ये रिजिव वायर बनाने की उम्मीद है।

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा

जेवर में स्थित नवादा गांव में चल रहे एक मिक्सर प्लाट को पर्यावरण विभाग द्वारा सील किया गया है। बताया जाता है कि गत के समय मिक्सर प्लाट चलाकर प्रदूषण की दुकान चलाने वाले विंडों से अमित कुमार अपनी अपनी दुकानों पर अवैध रूप से पटाखे बेच रहे हैं। सुचना के आधार पर पुलिस दीमी ने दोनों की दुकानों पर छापा मारा। इस दीमां यहां से बड़ी मात्रा में पटाखे बारमद हुए। थाना बदलाये गए प्रभारी ने बताया कि फैलाफ फैलाया जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद विभाग द्वारा यह घटना के बाद विभाग द्वारा यह बढ़ा दिया गया है।

कोरिं डेंडर साल से नवादा गांव में प्रतिवर्ष बारमद हुआ है। क्षेत्र में योगी डीड नाम के बाजारी में लिलाक तारकाली आदि को बजारी में लिलाक तारकाली लगाया जाता था। मौसम बदलने के कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए ग्रेप का नियम भी लागू है। जिसके बाद विभाग द्वारा यहां से तीन रिजिव वायर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक रिजिव वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

बर्ही, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तीन रिजिव वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजिव वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजिव वायर बनाना का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक ये रिजिव वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा दो गांवों पर छापा मारा। इस दीमां यहां से बड़ी मात्रा में पटाखे बारमद हुए। पूछाया गया में दोनों ने बताया कि बदलाये गए प्रभारी ने बताया कि फैलाफ फैलाया जा रहा था। उद्दीपने द्वारा यहां से बड़ी मात्रा में पटाखे बारमद हुए।

फैलाने से नहीं रुक रहे हैं। पर्यावरण लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर खड़ी और प्लाट को की सील किया गया है। उद्दीपने की दुकानों पर पटाखे बारमद हुए।

लोगों की शिकायत के बाद दीमा सोमवार को मौके पर







# पश्चिम एशिया

## युद्ध का बढ़ा खतरा

पश्चिम एशिया में अनेक मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है, हालांकि अमेरिका तनाव घटाने का प्रयास कर रहा है। हाल में ईरान पर इजराइली हवाई हमलों और बाद में जवाबी कार्रवाइयों ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टकराव को हवा दी है जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध का विस्तार हो सकता है। ईरानी आक्रमण की प्रतिक्रिया में इजराइल द्वारा ईरानी सैनिक ठिकानों पर हुए हवाई हमलों में चार ईरानी सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला ने फौरन उत्तरी इजराइल के आवासीय क्षेत्रों में अनेक राकेट दागे जिससे टकराव बढ़ने की संभावना पैदा हो गई है। युद्ध के वर्तमान चरण में आरोप है कि इजराइली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के सैनिक और राडार ठिकानों पर हमले के लिए ईराकी वायुक्षेत्र का प्रयोग किया। इजराइल इन कार्रवाइयों को ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खतरे को 'निष्प्रभावी' बनाने के नाम पर सही ठहराता है जिनमें लेबेनान के हिजबुल्ला शामिल हैं। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए निन्दा की तथा जवाब देने के अधिकार पर जोर दिया है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए इसकी 'लौह मजबूती' पर जोर दिया है। उसने आगे हमले करने के खिलाफ ईरान को कठोर चेतावनी भी दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुर्टेस ने तत्काल युद्ध रोकने का



पश्चिम एशिया की परस्पर जुड़ी राजनीति के संकेत मिलते हैं। शक्तिशाली मिलिशिया हिजबुल्ला के तेहरान से निकट संबंध हैं और वह इस क्षेत्र में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी है। उसकी संलिप्तता से संकेत मिलता है कि यह टकराव संभवतः इजराइल-ईरान के बीच द्विपक्षीय युद्ध से आगे बढ़ सकता है और इसमें अन्य राज्य व गैर-राज्य कारक भी शामिल हो सकते हैं। इस टकराव में अन्य देशों का शामिल होना खतरनाक होगा। लेबेनान पहले ही राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा है, अब वह युद्ध के मैदान में बदल कर पूरे 'लेवांत' को अस्थिर कर सकता है। इसी प्रकार इजराइली कर्रवाइयों के लिए अपना हवाई क्षेत्र देने में ईराक की कथित संलिप्तता से देश में शिया चरमपंथी संगठन सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ ही ईराक, सीरिया और यमन में ईरान के सहयोगी संगठन भी समन्वित रूप से इजराइल या क्षेत्र में अमेरिकी हितों के खिलाफ हमले कर सकते हैं। इससे टकराव सीमित करने के प्रयास और कठिन हो जाएंगे तथा अनेक मोर्चों पर असमान युद्ध छिड़ सकता है। इन स्थितियों में तत्काल ऐसे राजनीयक प्रयासों की आवश्यकता है जिनसे स्थिति को और बिंगड़ने से रोका जा सके। इजराइल को युद्ध से केवल अमेरिका विरत कर सकता है। वह युद्धविराम के लिए इजराइल को तैयार कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल व क्षेत्रीय सहयोगियों पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर उनको संयम बरतने को कह सकता है। इसके साथ ही वह ईरान को राजनीयक रूप से युद्ध भड़काने से रोक सकता है। वास्तव में, अमेरिका भी युद्ध के विस्तार के खिलाफ है। ऐसे में वाशिंगटन और तेहरान के बीच सोधा संपर्क युद्ध भड़काने वाली गलतफहमियां दूर कर सकता है। इसके अलावा भारत व रूस जैसी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां या ओमान जैसी क्षेत्रीय शक्तियां परोक्ष वार्ता के माध्यम से युद्धविराम का प्रयास कर सकती हैं। यह युद्ध हर कीमत पर रोका जाना चाहिए।

सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद नीतिगत बाधाओं तथा मूल्य सीमा के कारण ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति प्रभावित हो रही है।



तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय-एमपीएनजी के अंतर्गत पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में सितंबर, 2024 तक प्राकृतिक गैस-एनजी का भारत में उपभोग लगभग 12 प्रतिशत बढ़ा और यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36.850 बिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर-बीपीएमएससीएम पहुंच गया। लेकिन प्राकृतिक गैस या आमतौर से द्रव रूप में आयातित एलएनजी में इसी कालखंड में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 18.975 बीएमएससीएम तक पहुंच गया। उपभोग के प्रतिशत के रूप में यह अप्रैल-सितंबर, 2024 में 51.5 प्रतिशत हो गया, जबकि 2023 के इसी कालखंड में यह 46.8 प्रतिशत था। हालांकि, देश में



यह 46.8 प्रतिशत था। हालांकि, देश में अप्रैल-सितंबर, 2024 कालखंड में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। राज्य स्वामित्व वाले तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम-ओएनजीसी ने इस कालखंड में 9,407 बीएमएससीएम का उत्पादन किया जो पिछले वित्त वर्ष के इसी कालखंड की तुलना में 4 प्रतिशत कम था।

बीएमएससीएम का तत्त्व स्पौदन उत्पादन में

आएनजासा का कुल धरूल उत्पादन मयोगदान लगाभग 84 प्रतिशत है। लेकिन 8 प्रतिशत योगदान वाले आयल इंडिया लिमिटेड ने इस कालखंड में 4 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया और वह 1.577 बीएमएससीएम पहुंच गया। 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस का हिस्सा बर्तमान 6 प्रतिशत से बढ़ कर 15 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन 6 प्रतिशत हिस्से के लिए भी भारत को अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक आयात करना पड़ रहा है।

आज भी यह स्थिति नहीं बदली है।

कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 15 पतिशत करने के लिए इसके उपभोग में

वृद्धि कर इसे 184.222 बीएमएससीएम करना होगा, जबकि वर्तमान समय में यह 73.689 बीएमएससीएम है। वर्तमान उपभोग में 35.739 बीएमएससीएम का घरेलू उत्पादन शामिल है। यदि घरेलू उत्पादन वर्तमान स्तर पर ठहरा रहा तो 15 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एलएनजी का आयात बढ़ा कर 148.483 बीएमएससीएम करना होगा। इसका अर्थ है कि भारत को 80 प्रतिशत से अधिक आयात करना होगा और आयात निर्भरता बढ़ेगी। इस गणित में यह अनुमान शामिल है कि कुल ऊर्जा उपभोग में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यह तेज गति से बढ़ रहा है। देश में ऊर्जा की मांग में अगले पांच साल में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आशा है। इस परिदृश्य में प्राकृतिक गैस का 15 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आयात और बढ़ाना होगा। ऐसे में यह विचार करना उचित होगा कि उत्पादन बढ़ाने में क्या बाधा है।

भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारत में 26 'सेडीमेट्री बेसिन' हैं जिनका विस्तार 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इनमें हाइड्रोकार्बनों की खोज की जा सकती है। लेकिन इनमें से केवल 6 एसबी में वाणिज्यिक दोहन हो रहा है।

लगती है और यह तकनीक-केन्द्रित बिजनेस है जिसमें मुनाफा होने में बहुत लंबां समय लगता है। इसके साथ ही गहरी, बहुत गहरी व उच्च दाव तथा उच्च तापमान पर दोहन क्षेत्रों में डिलिंग बहुत जोखिम भरी होती है। यह बात खासकर कृष्णा-गोदावरी-केजी वेसिन जैसे क्षेत्रों के बारे में लालू होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में ही अधिकतम घंटार होने की आशा है। एक्सपानमेंटिल, चेवरान, टोटल, आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों-एमएनसी के पास ऐसी तकनीक और संसाधन हैं। इनको भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में दीर्घकालीन बोली बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को उनको 'टिकाऊ' आधार पर आकर्षक मुनाफों का प्रस्ताव दिया होगा। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एनजी क्षेत्रों में खोज व विकास के लिए उनके सामने कोई नियामकीय बाधा न हो और वे 'मुनाफे' वाली कीमतों पर गैस बेचने के लिए स्वतंत्र हों। मोदी सरकार ने अब तक नियामकीय बाधायें दूर करने में काफी प्रयास किए हैं। अभी हाल तक सुरक्षा कारणों से कुल 1.73 मिलियन वर्ग किलोमीटर आफशोर समुद्री क्षेत्रों में से 0.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर में अनुमति नहीं थी।

केंद्र ने लगभग इस परे क्षेत्र को दोहन

उत्पादन गतिविधियों के लिए खोला है। अब वह आवंटित क्षेत्रों के पूरे अधिकार देने वाली अधिकारी जीवन के लिए पढ़े के अधिकार दे रही है। इसका विस्तार 30 साल तक हो जाता है और उपलब्ध भंडार के आधार इसका विस्तार भी किया जा सकता है, कि पुरानी व्यवस्था में यह समय तथा तार का समय बहुत कम था। सरकार ने संरक्षण कानून में भी संशोधन कर ड्रोकार्बन खोज के लिए त्वरित पहुंच व्यवस्था की है। इसके लिए इड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पालिसी' -हेल्प जारी की गई है ऐसे 'ओपेन एकरेज लाइसेंसिंग पालिसी' -ओएएलपी, 2017 भी कहा गया है। इसके लिए फर्मों को अपनी पसंद क्षेत्र चुनने का अवसर भी दिया गया है, कि पहले उनको सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वीकार करना होता था। इसके साथ ओएएलपी के अंतर्गत आपरेटर को ग्राम लाइसेंस दिया जाता है जिसमें ड्रोकार्बन के सभी रूपों की खोज की समति होती है, फिर चाहे वे प्राकृतिक हों, 'शेल गैस' या कोल बेड र्मीथेन-चीएम आदि हों। लंबे समय से खोज एवं उत्पादन कंपनियां जटिल प्रक्रियाओं का कार्रार थीं जिनमें अनेक अनुमतियों, नशराही लाल फीताशही, आदि का हरण पर हस्तक्षेप होता था। एनईएलपी कीमत की सीमा प्रति एम्बीटीयू 6.50 डालर है जिससे यह फार्मूला बेकार हो गया है। अब नौकरशाहों ने ओएनजीसी व ओआईएल द्वारा की गई सप्लाई पर 20 प्रतिशत प्रीमियम की घोषणा की है जो केवल 'न्यू वेल्स' या 'वेल इंटरवेंशन्स' पर लागू होगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वे मूल्यों पर सीमारोपण कर अच्छी कीमतें देना चाहते हैं? इसके साथ ही 'न्यू वेल्स' या 'वेल इंटरवेंशन्स' का निर्धारण पूर्णतः उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। इस प्रकार कृष्णा-गोदावरी व आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां भी इनके दायरे में आ जाती हैं। ऐसे में तत्काल 'अनुमान योग्य' व 'आकर्षक' नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। किरीट पारिख समिति को ऐसी भावी समस्याओं का अनुमान था और उसने जटिल गैस क्षेत्रों को 1 जनवरी, 2026 तक 'वि-नियमित' करने तथा लोगों की क्षेत्रों से 1 जनवरी, 2027 से मूल्य नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था। सरकार को इन संस्तुतियों को लागू करना चाहिए। इसके साथ ही उसे प्राकृतिक गैस के बढ़े उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सप्लाई श्रृंखला में प्राकृतिक गैस जैसी आधारभूत चीजों का मल्य-नियंत्रण न करना पड़े।

# दैवीय ऊर्जा की तलाश

दिन से जुड़ी होती है, लेकिन इन ऊर्जाओं तक पहुंचने के लिए अनुशासनों का आवश्यकता नहीं होती है। योगिक और तांत्रिक परंपराओं में, केवल साधना हृषि शक्ति से जुड़ने की कुंजी है। प्रत्येक शक्तिका के रूप (स्वरूप) को समझना आवश्यक है। जबकि हर रूप का एक विशिष्ट नाम होता है, नाम केवल तभी प्रकट होते हैं जब शरीर विशेष साधनाओं के माध्यम से तैयार हो जाता है। बुनियादी स्तर पर, जब आपने गुरु के साथ ध्यान करते हैं, तो आप उनमें अलग-अलग रूप देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य या चंद्रमा। क्या आपने कधी सोच है कि ये रूप क्या दर्शाते हैं?



भी योगिक अध्यास को एक गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए जो इसे आपकी क्षमता के अनुसार अनुकूलित कर सके। इसी तरह, चंद्रमा एक आकर्षक ऊर्जा स्रोत है। यह केवल सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है, फिर भी यह पूर्णिमा के दौरान ज्वर और यहाँ तक कि पृथ्वी की सतह को भी प्रभावित कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा को क्या खास बनाता है? पूर्णिमा की रातों में, जानवर आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, और

दुर्घटनाओं और संघर्षों की घटनाएँ बढ़ाती हैं। ये केवल बुनियादी अवलोकन हैं जो इन खगोलीय रूपों के बारे में कुछ गहरी बात का संकेत देते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है, जो सनातन क्रिया के उचित अध्यास से प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमा शांत और शारीरिक पूर्ण लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में सूर्य की तुलना में अधिक अस्थिर है। जब आप गुरु के मार्गदर्शन में चंद्रमा का निरीक्षण करते हैं, तो

पाप इसके रूप में निहित मन्त्रों को समझ करते हैं। कुछ शक्तियाँ सीधे दिखाई नहीं आयी हैं और केवल अन्य शक्तियों के ध्याप से ही उन तक पहुँचा जा सकता है। अनुभव योग की नींव बनाते हैं। प्रत्यक्ष निरुभव के बिना, योग अधूरा रहता है। अकृति, अपने सभी अजूबों के साथ-भिन्न रंगों के फूलों से लेकर ऊपर के गाकाश तक-शक्तियों के छिपे हुए रूपों को माहित करती है। यदि आप बिना पलक यापकाए, गुरु के मार्गदर्शन में इन तत्वों का रीरक्षण करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि अपके शारीरिक और मानसिक असंतुलन दोहने लगे हैं। हालाँकि, अनुशासन (नियम) आवश्यक है। अभ्यास निरंतर ना चाहिए, और यदि किसी के पास शक्ति की क्षमता नहीं है या उसका मार्गदर्शन रने वाला कोई गुरु नहीं है, तो व्यवधान पन्न होंगे।

हमारे आस-पास की हर चीज़ में शक्ति सार होता है, और ये ऊर्जाएँ आसानी से लब्ध हैं। जब कोई व्यक्ति स्थिर हो जाता है और किसी विशेष शक्ति पर ध्यान केंद्रित रता है, तो वह उसका अनसरण करना शरू कर देती है, उसके जीवन को सशक्त बनाती है। दिवाली से पहले के नौ दिन विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान विशिष्ट शक्तियों का जमावड़ा होता है। हमारे पूर्वजों ने इन दिनों के दौरान शरीर को मजबूत बनाने और इन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी थी। इस दौरान, अपने मन को अपने भीतर केंद्रित रखें, क्योंकि इन नौ दिनों के दौरान की गई साधना महीनों के अभ्याससंकाल के बराबर होती है। जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आती है, खासकर अमावस्या (नए चंद्रमा की रात), जब हम दैये जलाते हैं, यह शक्ति साधना के लिए एक उपयुक्त समय होता है। यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति जो एक अनुभवी साधक नहीं है, वह भी ध्यान में आंखें बंद करके बैठकर शक्ति के स्वरूप को देख सकता है। शुद्ध हृदय से, कोई भी व्यक्ति बिना किसी विस्तृत अनुशासन के इन दिव्य ऊर्जाओं का अनुभव कर सकता है। इस दिवाली को शक्तिशाली शक्तियों से जुड़ने का समय बनाएं, उनकी उपस्थिति को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझूँ करें।

पात्र की वार्ता

गंगा का गार्भ

संघ का समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे उनके इस्तेवकतव्य का समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी किया है। संघ की अखिल भारतीय बैठक में सरकारीवाह दत्तात्रेय होसबले ने भी कहा है कि अगर हम एक नहीं हुए तो कटेंगे ही। उन्होंने कहा कि अगर भारत का हिन्दू समाज जाति, भाषा, प्रान्त, अगढ़ा, पिछड़ा में बेटे तो निश्चित ही कटेगा। संघ का समर्थन केवल योगी आदित्यनाथ के बयान के कारण न होकर अतीत की परिस्थितियों से मिले सबक के आधार पर भी है। हिंदुओं को विभिन्न जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों व संस्कृतियों के आधार पर बांटकर उनको गुलाम बनाने का प्रयास प्राचीनकाल से ही चल रहा है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी यही रणनीति अपनाई थी। आजादी के समय हुआ देश का बंटवारा भी बड़ी सीमा तक हिंदुओं में बिखारव के कारण हुआ था। विंडबना है कि आजादी के बाद जारी तुषीकरण व जातिवाद की नीतियों ने हिंदुओं में विभाजन बनाए रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश के साथ ही हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास तेज किए हैं। उम्मीद है कि इन प्रयासों को भविष्य में और बल मिलेगा।

विष्य में और बल मिलेगा।

मिलात ह की सार

दीपावली के पहले मिलावटी चीजों पर सरकार ने हर साल की तरह हमला बोला है। कहीं काजू नकली मिल रहे हैं तो कहीं मिठाइयों में कीड़े, कहीं खाने के तेलों में पापा आयल की मात्रा सीमा से अधिक मिल रही है तो कहीं नकली दूध के चर्चे हो रहे हैं। इन सब नकली चीजों से बीमारियां बढ़ने और स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है। हालांकि, दीपावली जैसे त्योहार के पहले खाद्य विभाग तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य सरकारी विभागों की कार्रवाई स्वगत योग्य है, लेकिन विडंबना है कि इसके बाद नकली चीजों पर मिटाइयों व अन्य खाद्य सामग्रियों की खपत बढ़ जाती है, लेकिन बाकी साल भर भी यह एक स्तर पर बनी रहती है। इसलिए जमीनी स्तर पर खाद्य विभाग को पूरे साल सक्रिय रहना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस और खुफिया विभाग को संगठित पैमाने पर बड़े मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग देना चाहिए। देश में जिस प्रकार भांति-भांति के माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार मिलावट-माफिया व नकली सामान-माफिया के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जनता का

पढ़ित यस्ता

दिल्ली में यमुना दूधित होती जा रही है जिस पर सभी समाचार पत्रों एवं टीवी में चर्चा भी जारी है। सभी जानते हैं कि दिल्ली की जनता को इससे पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन स्वयं यमुना का पानी ही साफ नहीं है। कई स्थानों पर झाग के रूप में यमुना नदी की गंदगी ऊपर आ चुकी हैं। यह दिल्ली के बातावरण को भी खराब करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनने पर ही कहा था कि हम यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना के पानी में विरोध स्वरूप डुबकी क्या लगाई, वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा। यह घटना बताती है कि दिल्ली की यमुना का प्रदूषण इतने बुरे स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, अतः यहां यमुना के साथ हवा का प्रदूषण देश को सारी दुनिया के सामने नीचा दिखाता है। ऐसे में बयानबाजी छोड़ कर यमुना को स्वच्छ बनाने की जरूरत है।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से











